लोकमत समाचार

भाषाई पत्रकारिता की अनदेखी नहीं की जा सकती: भारतीय

'भाषाई पत्रकारिता की प्रासंगिकता' विषय पर परिचर्चा आयोजित

मुंबई । 4 जनवरी । लोस सेवा

भाषाई अखबारों का अपने इलाकों में अच्छा-खासा असर होता है, क्योंकि वे आम आदमी की समस्याओं को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं. अंग्रेजी से यह बात संभव नहीं है. इसलिए भाषाई पत्रकारिता की अनदेखी नहीं कर सकते. यह विचार 'चौथी दुनिया' के संपादक संतोष भारतीय ने व्यक्त किए. वे मुंबई हिन्दी पत्रकार संघ द्वारा 'भाषाई पत्रकारिता की प्रासंगिकता' विषय पर आयोजित परिचर्चा में बोल रहे थे.

इस अवसर पर 'लोकमत समाचार' के संपादक विकास मिश्र ने कहा कि आजकल के दौर में भाषाई या क्षेत्रीय होना अपराध करने जैसा हो गया है. इस अपराधबोध से ऊपर उठने के लिए भाषाई पत्रकारों को अपने-आपको अधिक सक्षम बनाना होगा. केवल समाचार देना महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया है. समय की मांग के अनुसार सामग्री देना जरुरी हो गया है.

उन्होंने कहा कि भाषाई पत्रकारिता में कमी है, तो उसे ढूंढना होगा. आज ग्लैमर भी जरुरी है. कुछ हद तक क्षेत्रीय अखबारों की स्थिति खराब है. अखबार ग्रामीण भारत को भूल रहे हैं, लेकिन चाहे जो हो, हम संस्कार नहीं भूल सकते. इसलिए भाषाई पत्रकारिता बनी रहेगी. जो समस्या है, उससे उबरने के लिए गहराई से सोचना होगा. पत्रकारों को अधिक सक्षम बनने के लिए पढ़ने-लिखने पर जोर देना चाहिए.

'दोपहर का सामना' के निवासी संपादक अनिल तिवारी ने कहा कि आज राष्ट्रवाद पर केंद्रित मुखपत्र की जरुरत है. इसके चलते आम आदमी के सम्मान और संस्कार बने रहते हैं. पत्रकारिता की शुरुआत मिशन से हुई थी, जो बाद में पैशन में बदली. फिर फैशन हो गई और अब कमीशन तक आ गई. सकारात्मकता के साथ चला जाए तो भाषाई पत्रकारिता कभी खत्म नहीं हो सकती.

'न्यूज 18 लोकमत' के संपादक प्रसाद काथे ने कहा कि प्रासंगिकता का सवाल अभी नहीं बल्कि 2037 या 2047 के वक्त को ध्यान में रखकर करना होगा. लोग अपनी भाषाएं छोड़ रहे हैं. तब आने वाले दिनों में क्या होगा? उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा कि क्या हम समाज का मूल्यवर्द्धन कर रहे हैं? इन दिनों सिर्फ आंखें खुली रखने से काम नहीं चलेगा. ज्ञानचक्षु खुले रखने होंगे.

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि भाषाई पत्रकारिता के सामने कोई संकट नहीं है. उसकी स्वीकार्यता ज्यादा है, लेकिन यह फायदे का धंधा नहीं रहा. सरकार के 60 फीसदी विज्ञापन कथित राष्ट्रीय अखबारों के हिस्से में चले जाते हैं.

'मिड डे' (गुजराती) के पूर्व संपादक सौरभ शाह ने कहा कि अंग्रेजी की तर्ज पर भाषाई अखबारों में भी न्यूज और व्यूज एक साथ दिए जा रहे हैं. इसी कारण कथित राष्ट्रीय अखबार या चैनल एजेंडा सेट करने में सफल हो रहे हैं. इसके बावजूद भाषाई पत्रकारिता को कोई खतरा नहीं है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के हाथों मुंबई हिन्दी पत्रकार संघ की स्मारिका का विमोचन भी किया गया.